नदियों की रक्षा के प्रयास में सावधानी ज़रूरी

भारत डोगरा

हाल के समय में सरकार ने नदियों की रक्षा के जो वायदे किए हैं, उनका स्वागत होना चाहिए क्योंकि वास्तव में देश की अधिकांश नदियां बुरी तरह संकटग्रस्त हैं। कई नदियों का तो अस्तित्व ही खतरे में पड़ चुका है। इस स्थिति में नदियों की रक्षा के कार्य को व्यापक अभियान के रूप में आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है।

इस संदर्भ में सरकार के प्रयासों की कुछ सीमाओं और इन प्रयासों के लिए कुछ सावधानियों की ज़रूरत की ओर ध्यान दिलाना बहुत ज़रूरी है। केंद्र सरकार ने सबसे अधिक महत्व गंगा नदी की रक्षा को दिया है व अधिकांश घोषणाएं इसी संदर्भ में हुई हैं। गंगा नदी की रक्षा वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण है, पर साथ में अन्य नदियों की रक्षा भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतः ज़रूरत इस बात की है कि सभी नदियों की रक्षा की व्यापक समयबद्ध योजना बने। सबसे पहले बेशक गंगा नदी सम्बंधी कार्य किया जाए पर अन्य नदियों की भी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए।

गंगा नदी की योजना भी उसकी सहायक नदियों को ध्यान में रखते हुए व बहाव के पूरे क्षेत्र, जलग्रहण क्षेत्र तथा समुद्र से संगम क्षेत्र सभी को ध्यान में रखते हुए बननी चाहिए। यदि गंगा नदी के किनारे स्थित कुछ प्रमुख शहरों के आसपास यह प्रयास सीमित रहा तो इससे नदी की रक्षा का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सकेगा।

जहां एक ओर सरकार गंगा की रक्षा पर बहुत ज़ोर दे रही है, वहीं दूसरी ओर विभिन्न बांध-बैराज परियोजनाओं की स्वीकृति सम्बंधी पर्यावरणीय नियम-कानूनों को और कमज़ोर किया जा रहा है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रही तो इससे गंगा नदी व अन्य नदियों के लिए संकट कम होने के स्थान पर और बढ़ जाएगा। यदि उत्तराखंड में गंगा व उसकी सहायक नदियों पर सभी या अधिकांश प्रस्तावित बांध परियोजनाएं बनाई गईं तो उससे गंगा नदी का मूल रूप पूरी तरह नष्ट हो जाएगा व नदी के पानी की गुणवत्ता पर भी बहुत प्रतिकूल असर पड़ेगा।

इसके अतिरिक्त गंगा के मैदानी क्षेत्र में भी, विशेषकर इलाहबाद व हल्दिया के बीच, बहुत से बैराज बनाने की चर्चा गर्म है। एक प्रस्ताव यह है कि लगभग 100-100 किमी की दूरी पर बैराज बनाए जाएंगे जिसमें 1600 किमी के नदी बहाव की दूरी पर अनेक बैराज बनेंगे। यह सब एक गंगा जलमार्ग बनाने के लिए किया जा रहा है जिसमें बड़े जहाज़ चल सकें व माल की ढुलाई कम खर्च पर हो सके।

इस तरह व्यापारिक सोच को गंगा की रक्षा की सोच से ज़बरदस्ती मिलाया जा रहा है जो कि उचित नहीं है। इस तरह के प्रयास से हो सकता है कि व्यापारिक महत्व के कार्य आगे बढ़ जाएं जबकि गंगा की रक्षा का कार्य पीछे छूट जाए। इतना ही नहीं, इतने बैराजों के बनने से गंगा नदी का पर्यावरण बुरी तरह संकटग्रस्त हो सकता है।

गंगा नदी पर फरक्का बैराज बनने के हानिकारक परिणाम पहले ही सामने आ चुके हैं। इससे नदी के कटान की संभावना बहुत बढ़ गई है व नदी के आसपास के अनेक गांव व खेत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। बैराज बनने के बाद कई मछलियों व जल-जीवों पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ा है। मछलियों के लिए अपने प्रजनन क्षेत्र तक पहुंचना कठिन हुआ है। बैराज के पास गाद जमा होने के कारण नदी के पानी में मछलियों व जल-जीवों के लिए पोषक तत्व कम हुए हैं। जहां नदी समुद्र में मिलती है उस स्थान पर समुद्र के खारे पानी के आगे बढ़ने की संभावना अधिक हुई है।

जब एक ही बैराज के इतने प्रतिकूल असर सामने आए हैं तो बहुत से बैराज एक साथ बनने की स्थिति कितनी प्रतिकूल हो सकती है इसकी कल्पना की जा सकती है। इस तरह तो मैदानी क्षेत्रों में भी गंगा का प्राकृतिक प्रवाह बुरी तरह अवरुद्ध हो जाएगा। जगह-जगह बहुत मिट्टी-गाद निकालने के प्रयासों की ज़रूरत होगी जो ज़रूरी नहीं है कि असरदार सिद्ध हों। जल-प्रवाह अवरुद्ध होने से

प्रदूषण की समस्या व बाढ़ की समस्या दोनों पहले से और विकट हो सकती हैं। जल-जीवों के कम होने से भी प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी।

अतः बहुत सावधानी से इन सब संभावनाओं पर विचार करते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा उपचार के साथ मर्ज़ बढ़ता ही जाएगा।

सरकारी प्रयासों में कुछ उलझनें तो साफ नज़र आ रही हैं। एक ओर 'अविरल गंगा' का नारा दिया जा रहा है तो दूसरी ओर बांध-बैराज बहुत बढ़ाने की बात हो रही है। आखिर इस तरह की परस्पर विरोधी बातें क्यों कही जा रही हैं? सरकार की नीति स्पष्ट हो तो भागीदारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

प्रदूषण को रोकने का एक तरीका है कि नदी में मल-जल को न पहुंचने दिया जाए। अपितु एक उपयुक्त ऊंचे स्थान से इसे नीचे की ओर विशेष तौर पर बनाए तालाबों की ओर ले जाया जाए। ये तालाब एक-दूसरे से जुड़े हों। इन तालाबों में प्राकृतिक उपचार, विशेषकर सूर्य के प्रकाश के बेहतर उपयोग से मल-जल की अधिकतम सफाई की जाए। इस पानी को सुरक्षित हद तक साफ कर इसका उपयोग सिंचाई व खाद के लिए किया जा सकता है।

दूसरा अधिक विकेंद्रित उपाय यह है कि विभिन्न कालोनियों में ही वहां के मल-जल का उपचार किया जाए। इसके लिए विभिन्न कालोनियों में पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाया जाए। वहीं उपचार कर मल-जल को सिंचाई के पानी व खाद के रूप में उपयोग कर लिया जाए।

नदी के आसपास रहने वाले मछुआरों, मल्लाहों, केवटों, फल-सब्ज़ी उगाने वालों, दाह-संस्कार करने वालों आदि अनेक समुदायों को भी इन नदियों की रक्षा के प्रयासों से जोड़ना चाहिए। आसपास के किसानों को प्राकृतिक व आर्गेनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि नदी में कीटनाशक दवाओं, जंतुनाशक दवाओं व रासायनिक खाद का प्रदूषण न्यूनतम हो।

नदियों से ऐसे निर्मम खनन पर रोक लगनी चाहिए जिससे नदियों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है। नदियों को नुकसान पहुंचाए बिना कितनी बालू रेत ली जा सकती है, उतनी किसी भारी मशीन के उपयोग के बिना ली जा सकती है, पर उससे अधिक नहीं।

नदियों के जल-ग्रहण क्षेत्र में वनों व हरियाली की रक्षा ज़रूरी है। नदी के समुद्र से संगम स्थल का पर्यावरण बहुत संवेदनशील होता है। यहां की जैव-विविधता की रक्षा करने, जल-संतुलन बनाए रखने व खारे पानी को आगे बढ़ने से रोकने पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

नदियों व उनके आसपास के क्षेत्र में अनावश्यक व अवांछनीय छेड़छाड़ के प्रति सावधान रहना चाहिए। नदियों के प्राकृतिक प्रवाह का अपना पर्यावरणीय महत्व और औचित्य है। जब तक कोई विशेष व स्पष्ट वजह न हो, तब तक उससे अनावश्यक छेड़छाड़ से बचना चाहिए। नदी जोड़ योजनाएं बनाने से नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में बहुत बड़े स्तर पर बदलाव करने होंगे। नदियों पर बहुत तटबंध बनाने में भी कई समस्याएं हैं। इन सब तथ्यों व अनुभवों को ध्यान में रखते हुए सभी नदियों की रक्षा की एक समग्र योजना बननी चाहिए। ***(स्रोत फीचर्स)***